भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 840
जिसका उत्तर बुधवार 23 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

'फेम इंडिया' योजना

840. श्री डॉ. संजय सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने 'फेम इंडिया' योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के वाहनों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इस योजना के कार्यान्यवन के पश्चात् से अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या यह योजना अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सफल रही है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारत सरकार ने हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास तथा विनिर्माण परिस्थितिकी-तंत्र को सहायता देने के उद्देश्य से 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वयन हेतु फेम इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] अधिसूचित की है। इस योजना के चार फोकस क्षेत्र अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना हैं। इस योजना का चरण-I दो वर्ष की अवधि अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

फेम इंडिया योजना का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेंट्स अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियां जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

इस योजना की अधिसूचना भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इस योजना के लिए ₹75 करोड़ की धनराशि आबंटित की गई थी जिसका लगभग पूर्ण उपयोग कर लिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹122.90 करोड़ के बजट आबंटन में से ₹91 करोड़ (लगभग) का उपयोग किया जा चुका है।

01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने के पश्चात् इस योजना के तहत लगभग 99000 हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्सईवी) को मांग प्रोत्साहन के रूप में प्रत्यक्ष सहायता दी गई है। इस विभाग ने कुल लगभग ₹155 करोड़ की प्रायोगिक परियोजनाएं, चार्जिंग अवसंरचना परियोजनाएं और प्रौद्योगिकीय विकास परियोजनाएं भी अनुमोदित की हैं।

******